

बिहार की कोसी-मेची लकि परियोजना के नरिमाण का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों?

25 दसिंबर, 2022 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार बिहार की अतः महत्त्वाकांक्षी कोसी-मेची लकि परियोजना के नरिमाण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना का डीपीआर बनाने के लयि जल संसाधन वभिाग और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन वभिाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।

प्रमुख बढि

- कोसी-मेची लकि परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के चार ज़िलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सचिाई सुवधि और बाढ़ से राहत मलिंगी। इनमें पूर्णया, कटहिर, कशिनगंज और अररया ज़िला शामिल हैं।
- इस परियोजना से अररया ज़िले में करीब 69 हज़ार हेक्टेयर, पूर्णया ज़िले में करीब 69 हज़ार हेक्टेयर, कशिनगंज ज़िले में 39 हज़ार हेक्टेयर और कटहिर ज़िले में 35 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन की सचिाई होगी।
- कोसी-मेची लकि परियोजना से अररया ज़िले के अंतर्गत फारबसिगंज, कुरसाकाटा, सकिटी, पलासी, जोकीहाट एवं अररया प्रखंड को लाभ होगा। वहीं, कशिनगंज ज़िले के अंतर्गत टेढ़ागाछ, दधिलबैंक, बहादुरगंज एवं कोचाधामन प्रखंड को लाभ होगा।
- इसके अलावा पूर्णया ज़िले के अंतर्गत बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखंड तथा कटहिर ज़िले के अंतर्गत कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनहिरा एवं अमदाबाद प्रखंड लाभान्वति होंगे।
- वदिति है कि कोसी-मेची लकि परियोजना का काम शुरू करने के लयि पहले ही राज्य कैबनेट से मंजूरी मलि चुकी है। मई 2022 में ही राज्य सरकार ने डीपीआर गठन, सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लयि करीब दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक और खर्च की सवीकृति दे दी थी।
- राज्य सरकार द्वारा 90 फीसदी केंद्रांश की हो रही मांग तथा केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लयि केंद्रांश 60 फीसदी और राज्यांश 40 फीसदी के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी दी गई है।
- हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोसी-मेची लकि परियोजना के लयि भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लकि परियोजना की तरज़ पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान की मांग जारी है।
- इस परियोजना के अंतर्गत कुल लगभग 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जसिमें से 632 हेक्टेयर भूमि पूर्व से अधगृहीत है, जबकि 765 हेक्टेयर नज़ी भूमि का अधग्रहण कया जाना है।